

न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनूपीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

पील संख्या 7/2021

रामदेवसिंह पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी कंवरपुरा उम्र 64 वर्ष तहसील चिड़ावा जिला

झुझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार चिड़ावा।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.01.2021 न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा उनवानी सरकार बनाम
रामदेवसिंह मुकदमा नं0 25/20 अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

स्थिति:-

1. श्री शीशराम बोला, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय— अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से अपील आवेदन निम्नांकित प्रस्तुत है कि अपीलार्थी ने अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा के लिये खस्ता नम्बर 26 आम रास्ते की ओर पुख्ता दीवार का निर्माण 8 वर्षों पूर्व किया था जो कि आज दिनांक तक निर्विवाद चला आ रहा है। उक्त रास्ते की दूसरी दिशा में सुरजभान पुत्र रामराम जाति रैगर ने दिनांक 09.12.20 को उक्त रास्ते की भूमि में पुख्ता निर्माण करना शुरू कर दिया जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा करने पर पुलिस ने मौके पर आकर हल्का पटवारी को बुलाया तथा उक्त सुरजभान का काम बन्द करवा दिया था तथा दिनांक 09.12.20 को उक्त सुरजभान ने रात को ही उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर फिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो फिर ग्रामवासियों ने प्रतिपक्षी तहसीलदार चिड़ावा को सूचना दी तो दिनांक 10.12.20 को मौके पर पटवारी आया जिसके आने तक उक्त सुरजभान ने रास्ते की जमीन दबाकर करीब 1 से 2 फुट जमीन से उपर दीवार का निर्माण कर लिया तथा उक्त हल्का

4

जिला कलक्टर झुझुनू

2

वानी, गिरदावर आदि के आने के बाद बन्द कर दिया और उसने कहा कि अपीलान्ट ने ज़ा दबा रखा है इसकी दीवार तोड़ दो फिर अतिक्रमण हटा लूंगा। बहुत समझाने के बाद न ही मानने पर हल्का पटवारी व गिरदावर ने नपती कर रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर के से कहने पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके बाद उसने अपने प्रभाव से अपीलार्थी को यह नोटिस दिलवा दिया व अपीलार्थी की कृषि भूमि की सुरक्षा की दीवार लगभग एक मीटर रास्ते की ओर बताकर अपीलार्थी को यह नोटिस दिया गया जिसकी प्रथम तारीख पेशी दिनांक 21.12.20 दी गई थी। जिस पर अपीलार्थी ने उपस्थित होकर वकील नियुक्त किया गया वकील द्वारा जमीन की सीट की नकले मंगवाई थी जिसके लिये अपीलार्थी को दिनांक 21.01.21 दी थी उक्त दिनांक को अपीलार्थी ने उपस्थित न होकर परिवार में मौत होने के कारण अपने वकील को सूचित किया जिस पर आगामी दिनांक जबाब के लिये 21.01.21 में पत्रावली का उक्त अपीलग्रस्त निर्णय पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय विरुद्ध न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों व कानून के होने से प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है क्योंकि इस पत्रावली में कानूनी प्रक्रिया की कोई पालना किंचित भर भी नहीं की गई है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है अपीलार्थी को राजनैतिक द्वेषता रखने वालों की राय से अपीलार्थी को यह झुठा नोटिस दिलवाया गया है तथा न तो अपीलार्थी की जमीन की नपती ही की गई है तथा न ही अपीलार्थी को यह बताया गया है कि कितने फिट चौड़ा व कितने फुट लम्बा रास्ते में क्या कथित अतिक्रमण है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को कोई जबाब आदि के लिये अवसर ही दिया है इस प्रकार उक्त समस्त गैर कानूनी कार्यवाही पर आधारित उक्त निर्णय दिनांक 21.01.21 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.21 में अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करना लिखा है जो कतई न्यायोचित नहीं है जब उक्त निर्णय दिनांक की आर्डरशीट में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने ही लिखा है कि पत्रावली में त्रुटि हुई। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता उपस्थितफिर भी उक्त तथ्य अपने निर्णय में लिखकर महान कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय दिनांक की आर्डरशीट में तो अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को तो जबाब के लिये और अवसर देते हुए निर्णय लिया जाकर शामिल पत्रावली का आदेश है फिर बिना ओर तारीख के ही उक्त दिनांक को ही पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। अपीलार्थी को दिनांक 21.01.21 को जबाब हेतु अवसर दिनांक 25.01.21 दी गई थी जब उक्त दिनांक को अपीलार्थी के अधिवक्ता जबाब नोटिस लेकर गये तो सम्बन्धित लिपिक ने कहा कि आपकी पत्रावली में तो दिनांक 21.01.21 पूर्व की तारीख पेशी पर ही निर्णय कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी का अधिवक्ता उपयुक्त न्याय शुल्क पर पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिहवा का निर्णय दिनांक 21.01.21 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उम्मेदसिंह मु0नं0 25/20 निरस्त/अपास्त करने की कृपा करे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा स्थित भूमि ख0न0 26 रकबा 0.17 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते पर अपीलान्ट ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। दिवादित भूमि ख0न0 26 ख0न0 23 व ख0न0 29 के मध्य रास्ते के रूप में स्थित है।

६

अधीनस्थ न्यायालय

की का जो अतिक्रमण डण्डे के रूप में बताया गया है वह पुराना डण्डा है। फर्द मौका
 फर्द दिनांक 10.12.2020 के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अवैध कब्जा न होकर
 इमान का अवैध कब्जा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय
 इतीलदार चिड़ावा का निर्णय दिनांक 21.01.21 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उम्मेदसिंह
 नं० 25/20 निरस्त/अपास्त करने की कृपा करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि
 अपीलान्ट की गई भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर
 अपीलान्ट ने डण्डा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त
 है। वकील अपीलान्ट द्वारा जिस फर्द मौका रिपोर्ट का कथन किया जा रहा है वह
 अदालत मातहत की पत्रावली का हिस्सा नहीं है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट का अदालत मातहत
 आदेशिका में भी अंकन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह
 अदालत मातहत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण
 अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील में
 कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया।
 अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम कंवरपुरा स्थित भूमि ख0न0 26 रकबा 0.17 है0 किस्म
 गै0मु0 रास्ते में से 20 वर्गमीटर का अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट की भूमि भी विवादित भूमि से
 जुड़ी हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया है कि उनके मुवक्किल द्वारा अतिक्रमण
 किया गया है बल्कि उनकी खुद की जमीन है। मौके पर नपति करवाकर दिखवाले।
 इन वकील से सहमत होते हुए उक्त अतिक्रमण की पुनः नपति की जानी उचित है। अतः
 अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक
 21.01.2021 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को
 दी जाती है कि अदालत मातहत अपीलान्ट के खेत एवं रास्ते की नपति करें तथा फिर
 अतिक्रमण किया जाना पाया जावे तो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान
 करे। पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में
 नपति प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड
 अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर
 पंजिका से कम हो।

रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली
 शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
 जिला कलक्टर, झुंझुनूं
 25/02/21